GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION (GPM&AR) DEPARTMENT

Circular U.O. Note No. 46741/RTIA/GPM&AR/08-1, Dated. 19.12.2008

Sub:- Payment of fee under the RTI Act by demand draft/bankers cheque/Indian Postal Order.

Ref:- From the GOI, Ministry of Personnel, PG and Pension Department of Personnel and Training, New Delhi, Letter O.M. No. F.10/9/2008-IR, Dated: 5th December, 2008.

*****

A copy of the reference cited is communicated herewith to all the Departments of Secretariat, Heads of Departments and District Collectors for information and taking necessary action.

JAGANNATHA PRASAD MURTHY
SPL. CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT

To
All the Spl. CSs/Prl. Secys/Secys to Government (w.e)
All the Departments of Secretariat (w.e)
All the PIOs in GAD (w.e)
All the HODs (w.e)
All the District Collectors (w.e)

Copy to:
The Secretary
A.P. Information Commission,
HACA Bhavan,
Opp. Public Gardens,
Hyderabad.(w.e)
The Director General &
E.O. Spl. Chief Secretary to Govt,
Dr. MCR HRDI of AP,
Road No. 25, Jubilee Hills,
Hyderabad- 500 033.(w.e)
The Director General & Executive Director,
Centre for Good Governance,
Dr. MCR HRDI of AP Campus,
Road No. 25, Jubilee Hills,
Hyderabad – 500 033.(w.e)
The PS to Spl. CS to Government
GA (GPM&AR) Department.(w.e)
The PA to JS to Government
GA(GPM&AR) Department.(w.e)
Compendium file.

// FORWARDED :: BY ORDER //

19/12/08
Asst. Secretary to Government

No.F.10/9/2008-IR
Government of India
Ministry of Personnel, PG and Pension
Department of Personnel & Training

...

North Block, New Delhi
Dated: the 5th December, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of fee under the RTI Act by demand draft/bankers cheque/Indian Postal Order.

***

The undersigned is directed to say that the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005 provide that a person seeking information under the RTI Act, 2005 can make payment of fee for obtaining information by cash or demand draft or banker's cheque or Indian postal order. According to the rules the demand draft/banker's cheque /IPO should be payable to the Accounts Officer of the concerned public authority. It was brought to the notice of this Department that some public authorities did not accept demand drafts/banker's cheques/Indian Postal Orders drawn in the name of their Accounts Officer and insisted that these should be drawn in the name of Drawing and Disbursing Officer or the Under Secretary or the Section Officer etc. This Department vide OM No.1/2/2007-IR dated 23rd March, 2007 issued instructions that the demand drafts/banker's cheques/IPOs made payable to the Accounts Officers of the public authority should not be denied. Inspite of the provisions in the rules and instructions of this Department, some public authorities still refuse to accept demand drafts/banker's cheques /IPOs drawn in the name of the Accounts Officer of the public authority.

2. Refusal to accept an application on the ground that the demand draft/banker's cheque/IPO submitted by the applicant has been drawn in the name of the Accounts Officer may amount to refusal to accept the application. It may result into imposition of penalty by the Central Information Commission on the concerned Central Public Information Officer under Section 20 of the Act. All the public authorities should, therefore, ensure that payment of fee by demand draft/banker's cheque/IPO made payable to the Accounts Officer of the public authority is not denied.

3. Contents of this OM may be brought to the notice of all concerned.

(K.G. Verma)
Director
Tel: 23092158

1. All the Ministries / Departments of the Government of India
2. Union Public Service Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/

Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.

3. Central Information Commission/State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
5. O/o the Comptroller&Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All officers/Desks/Sections, DOP&T and Department of Pension & Pensioners Welfare.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.

संख्या : एफ.10/9/2008-आई.आर.

5

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001.

दिनांक : 5 दिसम्बर, 2008.

कार्यालय आदेश

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/इंडियन पोस्टल ऑर्डर द्वारा शुल्क का भुगतान ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम (शुल्क तथा लागत का नियमन) नियमावली, 2005 में यह प्रावधान है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने वाला व्यक्ति, सूचना प्राप्त करने के लिए नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक अथवा इंडियन पोस्टल आर्डर द्वारा शुल्क का भुगतान कर सकता है । नियमानुसार, डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/इंडियन पोस्टल आर्डर संबंधित लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय होना चाहिए । इस विभाग के नोटिस में यह लाया गया था कि कुछ लोक प्राधिकरण अपने लेखा अधिकारियों के नामे देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/इंडियन पोस्टल आर्डर को स्वीकार नहीं करते और यह आग्रह करते हैं कि यह भुगतान, आहरण और संवितरण अधिकारी अथवा अवर सचिव अथवा अनुभाग अधिकारी आदि के नाम पर आहरित होने चाहिए । इस विभाग ने दिनांक 23 मार्च, 2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/2007-आई.आर. द्वारा यह अनुदेश जारी किए कि लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/इंडियन पोस्टल आर्डर को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । नियमों में प्रावधान तथा इस विभाग के अनुदेशों के बावजूद अभी भी कुछ लोक प्राधिकरण अपने लेखा अधिकारियों के नाम आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/इंडियन पोस्टल आर्डर स्वीकार नहीं करते ।

2. इस आधार पर आवेदन स्वीकार न करना कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/इंडियन पोस्टल आर्डर लेखा अधिकारी के नाम पर आहरित किए गए हैं, का तात्पर्य आवेदन स्वीकार करने से इन्कार करना है । इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा संबंधित लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के तहत शास्ति लगाई जा सकती है । अतः सभी लोक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/इंडियन पोस्टल आर्डर द्वारा किए गए शुल्क के भुगतान को अस्वीकार न किया जाए ।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु सभी संबंधितों के नोटिस में लाई जाए ।

(के. जी. वर्मा)

निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग ।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी/ डेस्क/अनुभाग और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।

प्रति प्रेषित : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव